

मुकदमों का विवरण

मेसर्स आईएफसीआई लिमिटेड बनाम

सुतानु सिन्हा और ओआरएस।

(2023 की सिविल अपील संख्या 4929) 09 नवंबर, 2023

[संजय किशन कौल, सुधांशु धूलिया और अहसानउद्दीन अमानुल्लाह, जे. जे।]

हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: क्या "पुट विकल्प" के साथ अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर-सी. सी. डी. और विंडो अवधि के दौरान आई. सी. टी. एल.-उधारकर्ता की ओर से चूक की स्थिति में, वास्तव में एक ऋण कहा जा सकता है न कि एक इक्विटी।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 -धारा 62-उच्चतम न्यायालय में अपील-क्षेत्राधिकार यू/एस। 62 - अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर-सी. सी. डी. को ऋण या इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाना-तथ्यों पर, प्राधिकरण और आई. वी. आर. सी. एल.-आई. सी. टी. एल. के बीच रियायत समझौते के संदर्भ में प्रदान की गई परियोजना-आई. सी. टी. एल. आई. वी. आर. सी. एल. की एक सहायक कंपनी थी, जिसके पास आई. सी. टी. एल. की 100 प्रतिशत शेयर पूंजी थी-ऋणदाताओं के संघ ने आई. सी. टी. एल. को कंपनी ऋण समझौते को निष्पादित करने के लिए सावधि ऋण सुविधा प्रदान की, और शेष परियोजना को आई. वी. आर. सी. एल. द्वारा इक्विटी निवेश के माध्यम से वित्त पोषण किया जाना था-परियोजना के इक्विटी घटक के एक भाग के रूप में, अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर-सी. सी. डी.-सी. सी. डी. से इक्विटी में परिवर्तन की तारीख

280

मेसर्स आईएफसीआई लिमिटेड बनाम सुतानू सिन्हा एंड ओआरएस।

जो साधन अनिवार्य रूप से शेयरों में परिवर्तनीय है, उसे "इक्विटी" माना जाता है न कि ऋण या ऋण-शुद्धता।

आयोजित किया गया: आई. सी. टी. एल. का अपीलार्थी पर कोई दायित्व या दायित्व नहीं है क्योंकि अपीलार्थी वास्तव में एक इक्विटी प्रतिभागी है और उसके पास चुकाने के लिए कोई ऋण नहीं है-डिबेंचर सदस्यता समझौते में स्पष्ट रूप से आई. सी. टी. एल. को विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में परिभाषित किया गया है, जबकि आई. वी. आर. सी. एल. प्रायोजक कंपनी है और आई. एफ. सी. आई. ऋणदाता है-अपीलार्थी को डिबेंचर सदस्यता समझौते के तहत सुरक्षा प्रदान की गई थी, लेकिन दायित्व प्रायोजक कंपनी के हैं, यह आई. सी. टी. एल. का नहीं हो सकता है-जब तक कि

ऋण आई. सी. टी. एल. का नहीं है, अपीलार्थी आई. सी. टी. एल. का लेनदार होने के आधार पर राशि की वसूली की मांग नहीं कर सकता है-अनुबंध का अर्थ है-इसे पढ़ना या उसमें क्या जोड़ना मुश्किल है।⁶² – अधिकारिता दूसरी अपील के समान कानून के प्रश्न तक ही सीमित है-कानून में जांच के असीमित स्तरों की परिकल्पना नहीं की गई है और जांच के प्रत्येक स्तर के अपने मापदंड हैं-इस प्रकार, इस न्यायालय को प्रदत्त वैधानिक अधिकार क्षेत्र के दायरे के चार कोनों के भीतर पक्षों का विश्लेषण किया जाना चाहिए-अपील कानून के ऐसे किसी भी प्रश्न को नहीं उठाती है और यह कि नीचे दिए गए न्यायालयों के निर्णय तय किए गए सिद्धांतों के अनुसार हैं।[पैरा 14,16,20,21,23-26,30,31]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, **2016** -धारा **3 (11)**-ऋण की परिभाषा:

आयोजित किया गया:दावे के संबंध में दायित्व या दायित्व होगा जो किसी भी व्यक्ति को देय है-किसी वाणिज्यिक उद्यम की सफलता से उसे लाभ होता है

282

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

इक्विटी प्रतिभागी लेकिन आय के साथ, जो उद्यम की विफलता के मामले में नहीं होगी।[पैरा 14]

कार्य और दस्तावेज-वाणिज्यिक दस्तावेजों की व्याख्या:

आयोजित किया गया:वाणिज्यिक दस्तावेजों की जटिलताएं व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती हैं-ये आम आदमी के समझौते नहीं हैं, बल्कि विशेषज्ञों द्वारा जांचे गए समझौते हैं और इस प्रकार प्रत्येक पक्ष अपने दायित्वों और समझौते से उत्पन्न होने वाले लाभों को जानता है-अनुबंध का अर्थ है जैसा कि यह पढ़ता है-अदालत के लिए इसे पूरक या इसमें जोड़ना उचित नहीं है।[पैरा 21 और 23]

शहरों और
अन्य संदर्भों
की सूची

नरेंद्र कुमार माहेश्वरी बनाम भारत संघ और अन्य। (1990) पूरक।एस. सी. सी. 440; नाभा प्राइवेट लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य विद्युत निगम

सीमित [2017] 14 एस. सी. आर. 301-संदर्भित।क्रॉम्पटन एंड कंपनी लिमिटेड [1914] 1 Ch. 954-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2023 की सिविल अपील संख्या 4929।2023 के कंपनी अपील (एटी) (सीएच) (दिवाला) No.108 में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, चेन्नई के दिनांक 05.06.2023 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

विवेक चिब, वरिष्ठ अधिवक्ता, अमीश टंडन, समीर अभ्यंकर, सुश्री अनुश्री कुलकर्णी, सुश्री मानसी गुप्ता, सुश्री उन्नति झुनझुनवाला, ऋत्विक् माथुर, राहुल कुमार, हर्ष, आकाश ठाकुर, सुश्री निशी संगतानी, सुश्री वाणी वंदन छेत्री, आयुष बेओत्रा, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

श्याम दीवान, रामजी श्रीनिवासन, रितिन राय, वरिष्ठ अधिवक्ता।, साकेत शुक्ला, साहिल टागोत्रा, सुश्री नेहा नाइक, सुश्री माधवी दोशी, सुश्री सना लस्कर, सुश्री अभियक्ति बनर्जी, रोंगोन चौधरी, सुश्री पूजा महाजन, सुश्री कोमल अब्रोल, अविनाश बी. अमरनाथ, नमन गोलेचा, प्रतीक कुमार, सुश्री रवीना राय, रोहित घोष, सुश्री स्मृति नायर, अमन शुक्ला, मेसर्स खेतान एंड कंपनी, एड.उत्तरदाताओं के लिए।

283

मेसर्स आईएफसीआई लिमिटेड बनाम सुतानू सिन्हा एंड ओआरएस।

सर्वोच्च
न्यायालय का
निर्णय/आदेश

न्यायाधीश संजय किशन कौल, जे।

1. व्यापार का विकास हुआ है।वाणिज्य का आधार बनाने वाले दस्तावेज भी विकसित हुए हैं और दस्तावेजों की एक संकर प्रकृति का निर्माण किया है।इस प्रकार, जिसे पहले डिबेंचर के रूप में लेबल किया गया था, अब इसमें आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर, वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर और अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (सी. सी. डी.) जैसे संकर संस्करण हैं।हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि पारंपरिक रूप से डिबेंचरों को एक निश्चित तिथि पर भुगतान के लिए एक वाचा के साथ एक पूर्ण प्रतिभूति के रूप में माना जाता था।1

2. वर्तमान मामले के तथ्यात्मक परिदृश्य में, हम एक राजमार्ग परियोजना से संबंधित हैं जिसमें अपीलार्थी ने सी. सी. डी. के माध्यम से निवेश किया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन. एच. ए. आई.) ने अपने और आई. वी. आर. सी. एल. चेंगापल्ली टोलवेज लिमिटेड (आई. सी. टी. एल.) के बीच किए गए रियायती समझौते के संदर्भ में इस परियोजना को प्रदान किया था।आई. सी. टी. एल. आई. वी. आर. सी. एल. की एक सहायक कंपनी थी, जिसके पास आई. सी. टी. एल. की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। ऋणदाताओं के एक संघ ने आई. सी. टी. एल. को विभिन्न दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए सावधि ऋण सुविधा प्रदान की थी, जिसमें कंपनी ऋण समझौता दिनांक आई. डी. 1 शामिल था और शेष परियोजना को आई. वी. आर. सी. एल. द्वारा इक्विटी

निवेश के माध्यम से पूरा किया जाना था।परियोजना के इक्विटी घटक के एक हिस्से के रूप में, सी. सी. डी. के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त की जानी थी। यह विवाद में नहीं है कि अपीलार्थी ने जिस सी. सी. डी. की सदस्यता ली थी, हालाँकि अन्य डिबेंचरों को एक साथ निष्पादित किया जा रहा था।सी. सी. डी. से इक्विटी में परिवर्तन की तारीख दिसंबर, 2017 थी।हालांकि, उक्त तिथि के बाद शेयरों का औपचारिक निर्गमन नहीं किया गया था।हम ध्यान दे सकते हैं कि अपीलकर्ता आई. सी. टी. एल. के अनुरोध पर सी. सी. डी. की सदस्यता लेने के लिए सहमत हो गया था और Rs.125,00,00,000 की राशि-दिनांकित 14.10.2011 के डिबेंचर सदस्यता समझौते के संदर्भ में। उपरोक्त समझौते के संदर्भ में, एक "पुट विकल्प" था और इस प्रकार, विंडो अवधि के दौरान आई. सी. टी. एल. की ओर से चूक की स्थिति में, इन सी. सी. डी. को किसी तीसरे पक्ष को बेचा जा सकता था, लेकिन मुख्य दायित्व

1 क्रॉम्पटन एंड कंपनी लिमिटेड [1914] 1 Ch. 954।

284

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

आई. वी. आर. सी. एल. बना रहा।हालाँकि, इसके संबंध में तथ्यात्मक परिदृश्य कभी उत्पन्न नहीं हुआ।

3. ऐसा प्रतीत होता है कि यह परियोजना वित्तीय कठिनाइयों से ग्रस्त थी और आई. सी. टी. एल. ने एक बार के समझौते का भी सुझाव दिया था, जिस पर सहमति हो गई थी, लेकिन इसकी शर्तों का भी सम्मान नहीं किया गया था।अपीलार्थी द्वारा आई. वी. आर. सी. एल. की निगमित गारंटी लागू की गई थी।निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया अपीलार्थी और भारतीय स्टेट बैंक दोनों द्वारा शुरू की गई थी और दावे किए गए थे।दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (इसके बाद उक्त संहिता के रूप में संदर्भित) के तहत प्रक्रिया शुरू की गई थी।

4. अपीलार्थी ने दावा किया कि उसके लिए देय राशि ऋण की स्थिति में थी, और उस ओर से दावा दायर किया।हालाँकि, इसे रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा दिनांकित 09.08.2022 पत्र द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

5. दावा की गई पूरी राशि को अस्वीकार कर दिया गया था और गैर-प्रवेश के कारणों को यह नोट करने के बाद दर्ज किया गया था कि विभिन्न अंतर-पत्राचार और सहायक दस्तावेज प्रदान किए गए थे।अस्वीकृति के आधारों को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत करना प्रासंगिक होगा:-

“ए। आई. सी. टी. एल./कॉर्पोरेट देनदार, आई. वी. आर. सी. एल. लिमिटेड (पूर्ववर्ती आई. वी. आर. सी. एल.) के बीच 14 अक्टूबर, 2011 को किए गए डिबेंचर सदस्यता समझौते ("डी. एस. ए.") के अनुसार। एसेट्स एंड होल्डिंग्स लिमिटेड) और आईएफसीआई, अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर ("सीसीडी") को इक्विटी के रूप में माना जाना था।डी. एस. ए. की अनुसूची III के तहत इक्विटी के रूप में सी. सी. डी. घटक की रिकॉर्डिंग से भी यही देखा जाता है। आई.

सी. टी. एल./निगमित ऋणदाता और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ("एन. एच. ए. आई.") के बीच 25 मार्च, 2010 को हुए रियायत समझौते के लिए वित्तीय पैकेज के तहत सी. सी. डी. को इक्विटी के रूप में भी मंजूरी दी गई है।

बी। सी. सी. डी. एन. एच. ए. आई. द्वारा अनुमोदित परियोजना लागत में इक्विटी का हिस्सा थे और आई. वी. आर. सी. एल. लिमिटेड द्वारा ऋण इक्विटी अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता है। सी. सी. डी. का इक्विटी से ऋण में कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया गया था और जैसा कि आपके 19 मई, 2022 के ईमेल में कहा गया है, इस संबंध में एन. एच. ए. आई. से कोई मंजूरी नहीं ली गई थी। डी. एस. ए. मानता है कि रियायत समझौते का उल्लंघन करने वाला कोई भी कार्य अमान्य है।

ग. ऋणदाताओं के संघ ने सी. सी. डी. को इक्विटी के रूप में मानने की मंजूरी दी थी और एन. एच. ए. आई. से ऋण में परिवर्तन के लिए कोई मंजूरी नहीं मांगी गई थी।

285

मेसर्स आईएफसीआई लिमिटेड बनाम सुतानू सिन्हा एंड ओआरएस। [संजय किशन कौल, जे.]

286

घ. डी. एस. ए. के तहत सभी पुनर्भुगतान दायित्व आई. वी. आर. सी. एल. लिमिटेड के हैं न कि आई. सी. टी. एल./कॉर्पोरेट देनदार के।

ड. आई. सी. टी. एल./निगमित देनदार की तुलनपत्र के नोट यह भी स्पष्ट करते हैं कि पुनर्भुगतान दायित्व आई. वी. आर. सी. एल. लिमिटेड के हैं न कि आई. सी. टी. एल./निगमित देनदार के।

च. दिसंबर, 2017 में सीडी को अनिवार्य रूप से इक्विटी में परिवर्तित किया जा सकता था और रूपांतरण के लिए केवल कॉर्पोरेट कार्रवाई लंबित थी।”

6. उपर्युक्त से यह ध्यान दिया जाएगा कि ऋण दावे को अस्वीकार करने के लिए मौलिक मूलधन यह था कि अपीलार्थी द्वारा सी. सी. डी. के अनुसार राशि का निवेश करने को देखते हुए, इसे इक्विटी के रूप में माना जाना था। सी. सी. डी. को दिनांकित आई. डी. 1 के लिए वित्तीय पैकेज के तहत इक्विटी के रूप में अनुमोदित किया गया था और ये ऋण इक्विटी अनुपात वाले एन. एच. ए. आई. द्वारा अनुमोदित परियोजना लागत की इक्विटी के हिस्से के लिए थे। सी. सी. डी. का कभी भी इक्विटी से ऋण में कोई पुनः वर्गीकरण नहीं किया गया था। ऋणदाताओं के संघ ने इक्विटी के रूप में सी. सी. डी. की अवधि को भी मंजूरी दी थी। अपीलार्थी का समाधान पेशेवर की स्थिति को चुनौती देने का प्रयास आई. ए. No.1465/2022 द्वारा दिनांकित 14.03.2023 के आदेश के संदर्भ में सफल नहीं हुआ, उक्त आदेश इस न्यायालय के फैसले पर निर्भर था।

नरेंद्र कुमार माहेश्वरी बनाम भारत संघ और अन्य। 2 यह होगा

निर्णय के उस हिस्से को निकालने के लिए उपयोगी है जिसे राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) के विवादित आदेश में भी निकाला गया है जो इस प्रकार है:

“एक अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर सिद्धांत के किसी भी पुनर्भुगतान को स्वीकार नहीं करता है। प्रतिभूति का प्रश्न इन ऋणपत्रों पर ब्याज के भुगतान और सिद्धांत के भुगतान के उद्देश्य से केवल समाप्त होने की अप्रत्याशित स्थिति में ही प्रासंगिक हो जाता है। इसलिए, यह अपने क्लासिक अर्थों में 'डिबेंचर' का गठन नहीं करता है। यहां तक कि एक डिबेंचर, जो केवल विकल्प पर परिवर्तनीय है, को भी 'संकर' डिबेंचर माना गया है। कोई भी साधन जो अनिवार्य रूप से शेयरों में परिवर्तनीय है, उसे "इक्विटी" माना जाता है न कि ऋण या ऋण।”

(जोर दिया गया)

2 (1990) पूरक।एससीसी 440

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

7. हम ध्यान दे सकते हैं कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के उपरोक्त आदेश पर एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष आगे हमला किया गया था जिसने दिनांक 05.06.2023 के विवादित आदेश के अनुसार अपील को खारिज कर दिया था। इस बीच, लेनदारों की समिति (सी. ओ. सी.) ने 08.03.2023 पर अपनी मंजूरी दे दी, जिसके बाद न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने 01.05.2023 पर समाधान योजना को स्वीकार कर लिया। अपीलार्थी द्वारा इस पर विशेष रूप से हमला नहीं किया गया है। 8. अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुतियों का मूल आधार यह है कि अपीलार्थी को ऊँचा और सूखा छोड़ दिया गया है। यदि इसके निवेश को इक्विटी के रूप में माना जाए, तो झरने के सिद्धांत के तहत कुछ भी नहीं होगा। इस प्रकार, अन्य लेनदारों को लाभ होता है लेकिन अपीलार्थी को नहीं। यह पता चला है कि वरिष्ठ वकीलों का कहना है कि सी. सी. डी. के परिपक्व होने की प्रासंगिक तारीख के बाद भी, आई. सी. टी. एल. की वित्तीय बाधाओं के कारण इसे वास्तव में ऋण के रूप में माना जाता था। 9. वे प्रस्तुत करते हैं कि मुख्य मुद्दा यह है कि क्या अन्य दस्तावेजों के साथ सी. सी. डी. को वास्तव में एक ऋण कहा जा सकता है और सी. सी. डी. के शब्दों के बावजूद इक्विटी नहीं कहा जा सकता है, जिसे अन्य दस्तावेजों के साथ पढ़ा जाना चाहिए और पक्षों के बीच संचार किया जाना चाहिए। नरेंद्र कुमार माहेश्वरी के मामले (उपरोक्त) में निर्णय को इस आधार पर अलग करने की मांग की गई है कि यह एक जनहित याचिका के संदर्भ में था, और डिबेंचर की अवधारणा का उल्लेख किया गया है जो ऋण के चरित्र में आंतरिक रूप से हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के उद्देश्य से दस्तावेजों का एक समूह तैयार किया गया है और वास्तविक उद्देश्य यह था कि अग्रिम राशि को ऋण के रूप में माना जाए। आई. सी. टी. एल. के दिवालिया होने के कारण सी. सी. डी. का इक्विटी में रूपांतरण वास्तव में असंभव हो गया और इस प्रकार, ब्याज के साथ पूरी मूल राशि देय और देय हो गई।

10. विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क है कि वास्तव में अपीलार्थी को न तो शेयरधारक के रूप में माना जाता है और न ही एक वित्तीय लेनदार के रूप में माना जाता है जिससे अपीलार्थी को उपचार के बिना छोड़ दिया जाता है। उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि आई. सी. टी. एल. आई. वी. आर.

सी. एल. की एक सहायक कंपनी थी, जिसकी वास्तव में आई. सी. टी. एल. में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। 11. हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि उनके द्वारा यह विवादित नहीं है कि पुट विकल्प का कभी प्रयोग नहीं किया गया था। प्रभावी रूप से, उनका निवेदन था कि क्या सी. सी. डी. को ऋण या इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, यह सी. सी. डी. की परिपक्वता की स्थिति और उद्घाटन के समय निवेशक की स्थिति पर निर्भर करेगा, और यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में भिन्न होगा।

287

मेसर्स आईएफसीआई लिमिटेड बनाम सुतानू सिन्हा एंड ओआरएस। [संजय किशन कौल, जे.]

288

12. इस प्रस्तुतिकरण की सराहना करने के लिए, हम प्रतिवादी संख्या 1 के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील, Mr. Shyam दीवान के प्रस्तुतिकरण पर ध्यान दे सकते हैं, जिन्होंने एनएचएआई के साथ रियायत समझौते की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है।-

“इक्विटी” का अर्थ है भारतीय रुपये में व्यक्त राशि जो कुल परियोजना लागत के इक्विटी घटक को पूरा करने के लिए रियायत प्राप्तकर्ता की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का प्रतिनिधित्व करती है, और इस समझौते के उद्देश्यों के लिए परिवर्तनीय साधन या पूंजी के अन्य समान रूप शामिल होंगे, जो अनिवार्य रूप से कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तित हो जाएंगे, और ऐसी इक्विटी घटक को पूरा करने के लिए कंपनी के किसी भी शेयरधारक द्वारा दी गई कोई भी ब्याज मुक्त निधि, लेकिन इसमें इक्विटी समर्थन शामिल नहीं है।”

13. इस प्रकार, उनका कहना है कि सी. सी. डी. सहित परिवर्तनीय उपकरणों की अवधारणा इक्विटी की अवज्ञा के दायरे में आती है। अपने तर्क का समर्थन करने के लिए, उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ सामान्य ऋण समझौते का भी उल्लेख किया है, जिसमें कहा गया है कि उधारकर्ता को कोई भी डिबेंचर जारी करने या कोई भी ऋण जुटाने से पहले ऋणदाताओं की पूर्व लिखित मंजूरी की आवश्यकता होती है। हम श्री रामजी श्रीनिवासन, विद्वान वरिष्ठ वकील के प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में भी इस पहलू की सराहना कर सकते हैं कि ऋणदाताओं ने यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए थे कि उनके पूल का विस्तार न हो, जिसमें उनके ऋण की पूर्ण वसूली पर संदेह करने की क्षमता थी। इस प्रकार, जबकि ऋण इक्विटी अनुपात के लिए वित्त पोषण का 70 प्रतिशत ऋण की श्रेणी के तहत था, 30 प्रतिशत इक्विटी था और यह इक्विटी हिस्सा है जिसे आंशिक रूप से प्रारंभिक प्रवर्तकों द्वारा और शेष अपीलार्थी के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था। वित्तीय वित्तपोषण योजना ने स्वयं वित्त पोषण के इक्विटी भाग के हिस्से के रूप में सी. सी. डी. की परिकल्पना की। उपरोक्त प्रस्तुतियों को उक्त संहिता के संदर्भ में सराहा जाना चाहिए जहां धारा 3 अवज्ञा खंड है, और खंड 11 के अनुसार, ऋण जैसा कि नीचे दिया गया है:-

धारा 3 (11) “ऋण” का अर्थ है किसी दावे के संबंध में एक दायित्व या दायित्व जो किसी भी व्यक्ति से देय है और जिसमें वित्तीय ऋण और परिचालन ऋण शामिल हैं;

14. संहिता की धारा 3 (11) के तहत ऋण की अवज्ञा किसी भी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले दावे के संबंध में दायित्व या दायित्व होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

आई. सी. टी. एल. का अपीलार्थी के लिए कोई दायित्व या दायित्व नहीं है क्योंकि अपीलार्थी वास्तव में एक इक्विटी प्रतिभागी है और उसके पास चुकाने के लिए कोई ऋण नहीं है। एक वाणिज्यिक उद्यम की सफलता इक्विटी प्रतिभागियों को लाभ देती है, लेकिन आय के साथ, जो उद्यम की विफलता के मामले में नहीं होगी।

15. इस प्रकार, यदि यह एक सरल डिबेंचर होता, तो यह बॉन्ड आदि के साथ वित्तीय ऋण की श्रेणी में आता। हालाँकि, हम अपने आप में एक डिबेंचर से चिंतित नहीं हैं।

16. डिबेंचर सदस्यता समझौते में स्पष्ट रूप से आई. सी. टी. एल. को विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में परिभाषित किया गया है, जबकि आई. वी. आर. सी. एल. प्रायोजक कंपनी है और आई. एफ. सी. आई. ऋणदाता है। खंड 2.4 के संदर्भ में, 11 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज/कूपन दर, जो त्रैमासिक रूप से देय है, या तो सभी सी. सी. डी. (उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध एक विकल्प) की वापसी या सी. सी. डी. को इक्विटी में परिवर्तित करने तक लागू होती है। कूपन भुगतान करने के लिए देयता प्रायोजक कंपनी की है न कि एस. पी. वी./आई. सी. टी. एल. की। इसके अलावा, खंड 2.8 के तहत, पुनर्खरीद भी प्रायोजक कंपनी और आईएफसीआई के बीच एक व्यवस्था है। इक्विटी में रूपांतरण खंड 2.9 और पुट विकल्प खंड 2.11 के अनुसार होता है। यह खंड 2.9 को पुनः प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त होगा जो निम्नानुसार है:-

“ 2.9 इक्विटी में रूपांतरण

वापसी के भुगतान में चूक या करोड़ सी. सी. डी. की दो किश्तों में वापसी की स्थिति में, सी. सी. डी. जारी होने की तारीख से तीसरे वर्ष के अंत और छठे वर्ष के बीच किसी भी समय 15,50 प्रतिशत प्रति वर्ष का प्रभावी लेनदेन आई. आर. आर. (प्रायोजक कंपनी द्वारा देय प्रसंस्करण शुल्क सहित) दिया जाता है। यदि इसका उपयोग तीसरे और पांचवें वर्ष के बीच कभी भी किया जाता है, अन्यथा 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर, सदस्यता/प्रथम संवितरण की तारीख से पांचवें और छठे वर्ष के बीच लागू होगी (जिसमें प्रायोजक कंपनी द्वारा देय अग्रिम ब्याज भी शामिल है), बकाया सी. सी. डी., अलग-अलग ब्याज, चूक राशि आदि के साथ स्वचालित रूप से आई. सी. टी. एल. के प्रवर्तकों के बराबर कीमत पर आई. सी. टी. एल. के इक्विटी शेयरों में परिवर्तित हो जाएंगे, यानी जारी होने की तारीख से 6 साल के अंत में प्रति शेयर Rs.90 के प्रीमियम पर (यानी यदि प्रायोजक द्वारा कॉल और पुल विकल्प दोनों का उपयोग नहीं किया जाता है)।)”

17. उपरोक्त खंड इस प्रकार संबंधित तिथि पर आईसीटीएल के इक्विटी शेयरों में स्वचालित रूपांतरण का प्रावधान करता है जिसके लिए कोई विवाद नहीं है अर्थात् 09.11.2017।

18. अपीलार्थी को सुरक्षित करने के लिए, हमें यह बताया गया है कि खंड 3.1 डिबेंचरों के लिए प्रतिभूति प्रदान करता है। खंड 3.1 निम्नानुसार है:-

“ 3.1 ऋणपत्रों के लिए प्रतिभूति

इस समझौते के तहत उक्त डिबेंचरों के संबंध में आईएफसीआई को देय ब्याज, लागत, शुल्क, व्यय और अन्य शुल्कों के साथ डिबेंचर निम्नलिखित द्वारा सुरक्षित किए जाएंगे:

क) आई. वी. आर. सी. एल. एसेट्स एंड होल्डिंग्स लिमिटेड अर्थात् प्रायोजक कंपनी की बिना शर्त और अपरिवर्तनीय कॉर्पोरेट गारंटी,

ख) प्रायोजक कंपनी द्वारा रखे गए आई. सी. टी. एल. के डीमैट रूप में शेयरों की प्रतिज्ञा, जो एस. पी. वी. कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी का 49 प्रतिशत से कम नहीं है, को वित्त पोषण के पूरे कार्यकाल के दौरान बनाए रखा जाएगा। हालांकि, प्रतिज्ञा का आह्वान तभी किया जाएगा जब आई. वी. आर. सी. एल. एसेट्स एंड होल्डिंग्स लिमिटेड, प्रायोजक कंपनी, अपने गारंटी दायित्व का सम्मान करने में विफल रहती है।

ग) एक वचन दें कि परियोजना के वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा सुरक्षित रूप से लागू किए जाने के मामले में, आईएफसीआई के पास एस्क्रो समझौते के अनुसार सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद प्रायोजक कंपनी के पास उपलब्ध अवशिष्ट पर शुल्क होगा, और आईसीटीएल अपने द्वारा प्राप्त कुल आय को आईएफसीआई लिमिटेड द्वारा सुझाए गए एक अलग खाते के माध्यम से भेजेगा। 19. हम खंड 3.3 पर भी ध्यान दे सकते हैं जो रियायत समझौते के एक अधिस्थापक प्रभाव का प्रावधान करता है और उसी का खंड (बी) नीचे दिया गया है:-

“ 3.3 रियायत समझौते के प्रभाव को ओवरराइड करना:

बी) इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत के बावजूद, और हमेशा रियायती समझौते की समग्र सर्वोच्चता के अधीन, पार्टियां यहां पुट विकल्प को लागू नहीं करने और/या अन्यथा केवल प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कार्रवाई करने के लिए सहमत हैं; एनएचएआई की पूर्व लिखित मंजूरी के बिना जब ऐसा कोई एकल और/या एकाधिक

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

इस समझौते और/या शपथ समझौते के तहत एक साथ या अन्यथा किए गए कार्य (ओं), जिसे पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ संयुक्त रूप से या अलग-अलग पढ़ा जाता है, रियायत समझौते के खंड 5.3 के अनुसार स्वामित्व में परिवर्तन का गठन करता है। यदि ऐसा कोई भी कार्य एन. एच. ए. आई. की पूर्व लिखित मंजूरी के बिना किया जाता है, तो उसे रियायती समझौते के उल्लंघन में किया गया माना जाएगा और इस प्रकार उपरोक्त उपखंड (ए) के अनुसार शुरुआत से ही अमान्य माना जाएगा। एतद्वारा यह विनिर्दिष्ट रूप से स्पष्ट किया जाता है कि रियायत समझौते के तहत 'स्वामित्व में परिवर्तन' के उद्देश्यों और खंड 5.3 में प्रदान की गई अन्य बातों के साथ-साथ सभी शर्तों के लिए, ऋणदाता (आईएफसीआई) को हर समय इक्विटी के 'अधिग्रहणकर्ता' के रूप में माना जाएगा और/या वह व्यक्ति जो प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से उधारकर्ता (रियायतकर्ता) के निदेशक मंडल का नियंत्रण प्राप्त कर रहा है।”

20. उपरोक्त सभी को पढ़ने से यह निष्कर्ष निकलता है कि अपीलार्थी को डिबेंचर सदस्यता समझौते के तहत प्रतिभूति प्रदान की गई थी, लेकिन दायित्व प्रायोजक कंपनी के हैं। यह स्थिति होने के कारण, हमारे लिए यह समझना मुश्किल है कि एस. पी. वी. यानी आई. सी. टी. एल. का दायित्व कैसा है। जब तक ऋण आई. सी. टी. एल. का नहीं है, तब तक अपीलकर्ता एस. पी. वी. आई. सी. टी. एल. का लेनदार होने के आधार पर राशि की वसूली की मांग नहीं कर सकता है।

21. हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि व्यावसायिक दस्तावेजों की जटिलताएं व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। ये आम आदमी के समझौते नहीं हैं, बल्कि विशेषज्ञों द्वारा जांचे गए समझौते हैं और इस प्रकार प्रत्येक पक्ष अपने दायित्वों और समझौते से उत्पन्न होने वाले लाभों को जानता है। इस प्रकार हम यह समझते हैं कि सी. सी. डी. के बारे में दस्तावेज क्या कहता है, इसे पढ़ना या उसमें जोड़ना मुश्किल है। 22. हमारे लिए यह कहना पर्याप्त है कि वाणिज्यिक की व्याख्या का पहलू

नाभा प्राइवेट लिमिटेड बनाम पंजाब में दस्तावेजों का गहन विश्लेषण किया गया था।

स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 3. हमारे सामने मौजूद तथ्यात्मक परिदृश्य के संबंध में, पैरा 72 को निम्नानुसार निकालना पर्याप्त होगा:

“72. हालाँकि, हम अंत में सावधानी के एक शब्द का विस्तार कर सकते हैं। यह निश्चित रूप से वाणिज्यिक न्यायालयों का अनुबंध की निहित शर्तों को देखने का प्रयास नहीं होना चाहिए। वर्तमान समय और युग में अनुबंध बनाना सभी पक्षों के कानूनी दिमाग के साथ उच्च तकनीकी विशेषज्ञता का विषय है

3 (2018) 11 एससीसी 508 291

मेसर्स आईएफसीआई लिमिटेड बनाम सुतानू सिन्हा एंड ओआरएस। [संजय किशन कौल, जे.]

292

एक अनुबंध का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल। इससे पहले स्पष्टीकरण और संदेह मांगने के अवसर भी मिलते हैं ताकि पक्षों को पता चले कि वे क्या कर रहे हैं। इस प्रकार, आम तौर पर एक

अनुबंध को उसकी स्पष्ट शर्तों के अनुसार पढ़ा जाना चाहिए। निहित शब्द एक अवधारणा है, जिसकी आवश्यकता केवल तभी होती है जब उल्लिखित पेंटा परीक्षण लागू होता है। इसकी सख्त जरूरत है। वर्तमान मामले में, हमने वास्तव में अनुबंध को केवल उसी तरीके से पढ़ा है जैसे वह पढ़ता है। हमने वास्तव में इसमें किसी भी "निहित शब्द" को नहीं पढ़ा है, लेकिन खंडों के संग्रह से, एक निष्कर्ष पर आते हैं कि अनुबंध क्या कहता है। हमारे विचार से ऊर्जा आवेशों का सूत्र काफी स्पष्ट था। हमने अनुबंध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए केवल इसकी प्राकृतिक व्याकरणिक आकृति के अनुसार इसकी व्याख्या की है।”

23. उपरोक्त का प्रभाव यह है कि एक अनुबंध का अर्थ है जैसा वह पढ़ता है। न्यायालय के लिए यह सलाह नहीं दी जाती है कि वह इसे पूरक बनाए या इसमें जोड़ दे। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण परिदृश्य है जहां अपीलार्थी को ऊँचा और सूखा छोड़ दिया जा रहा है क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वह प्रायोजक कंपनी से वसूली कर सके, कोई संपत्ति और धन नहीं है। जबकि आई. सी. टी. एल. में इसे एक शेयरधारक के रूप में माना जा रहा है और इस प्रकार, इससे कोई लाभ नहीं होता है क्योंकि किसी भी शेयरधारक यानी मूल निवेशक और अपीलार्थी को उस योजना के तहत कोई लाभ नहीं मिलता है जिसे अनुमोदित किया गया है। सौंपा गया ऋण कम दर का था, जिसे किसी तीसरे पक्ष द्वारा फिर से खरीदा गया था। हालाँकि, ये संबंधित पक्षों के व्यावसायिक निर्णय हैं। खंड 2.4 के संदर्भ में दायित्व प्रायोजक कंपनी और आई. वी. आर. सी. एल. के थे। 24. आक्षेपित निर्णय को पढ़ने से, विशेष रूप से पैरा 19 के बाद के तर्क से पता चलता है कि इस मुद्दे को सही ढंग से स्पष्ट किया गया है कि क्या सी. सी. डी. को इक्विटी साधन के बजाय ऋण के रूप में माना जा सकता है। इस मायने में, यह देखा गया कि उन्हें ऋण के रूप में मानना रियायती समझौते और सामान्य ऋण समझौते के उल्लंघन के समान होगा। निवेश स्पष्ट रूप से डिबेंचरों की प्रकृति में था जो अनिवार्य रूप से इक्विटी में परिवर्तनीय थे और कहीं भी यह निर्धारित नहीं किया गया है कि ये सी. सी. डी. किसी विशेष घटना के होने पर वित्तीय ऋण के रूप में भाग लेंगे। 25. अपीलार्थी ने गारंटी का आह्वान किया है और प्रायोजक कंपनी के खिलाफ उपाय की मांग की है। यह तथ्य कि यह किसी भी सार्थक उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा नहीं है जो हमारे साथ वजन कर सकता है।

26. विवादित आदेश में एक महत्वपूर्ण पहलू जिस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है, वह यह है कि विभिन्न समझौतों की शर्तों ने निगमित देनदार को ऋण लेने से रोक दिया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

समनुदेशकों की सहमति के बिना अतिरिक्त ऋण। ऐसी कोई मंजूरी नहीं मांगी गई या नहीं ली गई। इस राशि को केवल इक्विटी के रूप में माना जाता था न कि ऋण के रूप में। 27. एन. सी. एल. ए. टी. ने उस उपचार के मुद्दे को भी छुआ है जो अपीलार्थी के लिए उपलब्ध था, जो उसके विचार में, संहिता में सार होने के कारण समयबद्ध प्रक्रिया के भीतर लाभ नहीं उठाया गया था। अपीलार्थी के दावे को 09.08.2022 पर खारिज कर दिया गया था और अपीलार्थी ने केवल इस मुद्दे को फिर से उठाने की मांग की थी जो समय की अवधि को बढ़ा नहीं सका।

28. अस्वीकृति के लिए चुनौती केवल 30.11.2022 पर रखी गई थी, दावे की अस्वीकृति के तीन महीने की अवधि के बाद।

29. अंत में, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा अधिकार क्षेत्र संहिता की धारा 62 से आता है। उक्त खंड निम्नानुसार है:

“62.(1) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर इस संहिता के तहत ऐसे आदेश से उत्पन्न कानून के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है।

30. अधिकार क्षेत्र दूसरी अपील के समान कानून के प्रश्न तक सीमित है। कानून में जांच के असीमित स्तरों की परिकल्पना नहीं की गई है और जांच के प्रत्येक स्तर के अपने मापदंड हैं। इस प्रकार, इस न्यायालय को प्रदत्त वैधानिक अधिकार क्षेत्र के दायरे के चार कोनों के भीतर पक्षों का विश्लेषण किया जाना चाहिए।

31. इस प्रकार हमारा विचार है कि अपील कानून का ऐसा कोई सवाल नहीं उठाती है और नीचे दिए गए न्यायालयों के निर्णय तय किए गए सिद्धांतों के अनुसार हैं।

32. हम इस प्रकार अपील को खारिज करते हैं और पक्षों को अपना खर्च खुद वहन करने के लिए छोड़ देते हैं।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

याचिका खारिज कर दी गई।

निधि जैन